बबल एन. सी. जैन, वी. *के. बाली और स्वतंत्र कुमार* के समक्ष

, जे.जे.

चंचलेश और अन्य, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

भूमि ग्रहण कलेक्टर और अन्य - *उत्तरदाता।*
सी.डब्ल्यू.पी. 1992 का 15043

18 जुलाई, 1996

भारत का संविधान, अनुच्छेद 226/221 - भूमि अधिग्रहण अधिनियम - भूमि मालिकों ने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ दायर किया - कलेक्टर के पुरस्कार ने लाभ देने को बरकरार रखा - जिला न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर कोई अपील नहीं - अन्य भूस्वामियों ने अपील दायर की। ऐसे भूमि मालिकों को मुआवजे में वृद्धि का दावा करना या क्या धारा 28-ए के तहत वृद्धि दी जानी है, जिन्होंने धारा 18 संदर्भ के तहत दायर नहीं किया है - धारा 18 के स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय मामले के औचित्य पर विचार करने के लिए अनिच्छुक होगा।

अधिनियम की धारा 28-ए में उपयोग किए गए शब्दों का सीधा अर्थ यह है कि केवल ऐसे व्यक्ति ही पुन: निर्धारण के हकदार हैं जिन्होंने पहले अधिनियम की धारा 18 के तहत कलेक्टर को आवेदन दायर नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, ऐसे पीड़ित व्यक्ति *जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत कलेक्टर के समक्ष आवेदन दायर नहीं किया था, वे अधिनियम की धारा 28-ए को लागू करने के हकदार हो जाते हैं। अधिनियम की धारा 28-ए में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल उन व्यक्तियों को अधिनियम की धारा* 28-ए के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार है जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग नहीं की है। ऐसे भूस्वामी जिन्होंने संदर्भ के लिए आवेदन नहीं किया था, उन्हें अन्य भूस्वामियों के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग की थी। धारा के स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय मामले के औचित्य पर विचार करने के लिए अनिच्छुक होगा।

(Para 9)

इसके अलावा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बबुआ राम के मामले में मेवा राम के मामले और अनुसूचित जाति सहकारी भूमि स्वामित्व समिति के मामले को विस्तृत रूप से संदर्भित करने के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि अधिनियम की धारा 28-ए की उप-धारा (1) केवल प्रति पुत्र पर लागू होगी - जो अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ प्राप्त करने और सुरक्षित करने में विफल रहा - धारा 4 (1) के तहत प्रकाशित उसी अधिसूचना के तहत कवर की गई भूमि में समान रूप से रुचि रखने वाले व्यक्ति। अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ पर प्राप्त अधिनियम अधिनियम की धारा 26 के तहत एक पुरस्कार में उच्च मुआवजा प्रदान करता है। भूस्वामियों

के अन्य विद्वान वकील ोंं ने तर्क दिया कि सभी भूस्वामी चाहे वे अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ चाहते हों या नहीं, उनके साथ समान स्तर पर व्यवहार किया जाना चाहिए और यह कि अलग-अलग व्यवहार करने का कोई औचित्य नहीं है, बबुआ राम के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जवाब दिया गया है। यह भी माना गया है कि अधिनियम की धारा 28-ए न्यायसंगत और निष्पक्ष है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है।

(Para 12)

इसके अलावा, यह माना गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर और अधिनियम की धारा 18 के स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से दोहराया जा सकता है कि धारा 28-ए केवल उन दावेदारों पर लागू होगी जो अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ प्राप्त करने में विफल रहते हैं। जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा था कि क्या ऐसे भू-स्वामी अंततः उच्च न्यायालयों में अपील में गए थे या नहीं। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 28-ए के तहत पुनर्निर्धारण का अधिकार केवल उन भूमि मालिकों तक ही सीमित है, जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ नहीं मांगा था। अनुसूचित जाति सहकारी भूमि स्वामित्व समिति लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के मद्देनजर भूमि मालिकों के एक समूह के बीच भेदभाव के बिंदु पर याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील, जिन्होंने संदर्भ प्राप्त नहीं किया और इसके पीछे तर्क को बिल्कुल भी बल नहीं मिला है।

(Para 14)

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मणि राम और आरके बट्टस।

हरियाणा राज्य की ओर से जसवंत जैन, अधिवक्ता, *उत्तरदाताओं के लिए।*

पंजाब के एडवोकेट जनरल एम. एल. सरीन, प्रतिवादी की ओर से पंजाब की डीएजी सुश्री चारू तुली के साथ।

निर्णय

एन. सी. जैन, जे.

1. हमारा यह निर्णय 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 15043, 1991 की 16853 और 15196 का निपटारा करेगा क्योंकि इन सभी याचिकाओं में कानून का समान प्रश्न उत्पन्न हुआ है।

1. पक्षकारों के विद्वान वकील इस बात से सहमत हैं कि मामले के तथ्यों को 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 15043 (चंचलेश और अन्य *बनाम* भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य) से उठाया जाए, हालांकि संदर्भ आदेश सिविल रिट में पारित किया गया है।

1991 की याचिका संख्या 16853 (हरि राम और अन्य *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य)। तदनुसार हम श्रीमती चंचलेश मामले से मामले के तथ्यों को उठाएंगे।

2. एक आम अधिसूचना के आधार पर, याचिकाकर्ताओं की भूमि के साथ-साथ अन्य भूमि-मालिकों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 28 मई, 1983 को 9,600 रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन करते हुए एक पुरस्कार दिया। याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अन्य भूमि मालिकों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत संदर्भ की मांग की। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने कलेक्टर के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन 1984 के अधिनियम संख्या 68 द्वारा प्रमुख अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार बढ़ी हुई सहायता, ब्याज आदि के रूप में कुछ वैधानिक लाभ प्रदान किए। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की। हालांकि, कुछ भूस्वामियों के कहने पर इस न्यायालय में वृद्धि की गई थी। रिट याचिका में मुआवजे की सटीक बढ़ी हुई राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने, कोई अपील दायर नहीं की है, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार मुआवजे के पुनर्निर्धारण के लिए अधिनियम की धारा 28-ए के तहत एक आवेदन दायर किया। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि अधिनियम की धारा 28-ए के प्रावधान केवल उन भूस्वामियों को राहत देने के लिए हैं जो किसी भी कारण से अधिनियम की धारा 18 के तहत अपने आवेदन दायर नहीं कर सके।

1. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, जो बहस के दौरान विवादित नहीं थी और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के आदेश को ध्यान में रखते हुए, इन सभी मामलों में जो सटीक प्रश्न उठा है, वह यह है कि क्या ऐसे भूमि मालिक जिन्होंने कलेक्टर के फैसले के बाद अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ दायर किए थे, वे उच्च न्यायालय द्वारा की गई वृद्धि के आधार पर बढ़े हुए मुआवजे का दावा करने के भी हकदार हैं या केवल ऐसे भूमि मालिक बढ़े हुए मुआवजे के अनुदान के हकदार हैं जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत जिला न्यायाधीश की अदालत से संपर्क नहीं किया है।

2. इस स्तर पर, 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 168531 में पूर्ण पीठ को दिए गए संदर्भ पर एक नज़र डालना आवश्यक है, जिसे हमारे द्वारा उपरोक्त मामले के रिकॉर्ड से निकाला गया है। संदर्भ आदेश निम्नानुसार है: –

"स्वीकार किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील श्री मणि राम का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपात

मेवा राम (L.Rs द्वारा मृत) *और* अन्य बनाम मेवा *राम में अदालत* । *हरियाणा राज्य,* ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 45 उस मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है जहां याचिकाकर्ताओं के भूस्वामियों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत संदर्भ प्रस्तुत किया था और जिला न्यायाधीश के निर्णय के बाद अधिनियम की धारा 28-ए के तहत बढ़े हुए मुआवजे का दावा करने के लिए कोई अपील दायर नहीं की थी। उपरोक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय की

कतिपय टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर अपील को खारिज करते समय एक पारित संदर्भ दिया गया था कि वे अधिनियम की धारा 28-ए के तहत मुआवजा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तर्क यह है कि चूंकि जिन व्यक्तियों ने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ दायर नहीं किया था, उन्हें कलेक्टर के पास जाकर अधिनियम की धारा 28-ए के तहत बढ़े हुए मुआवजे का दावा करने का अधिकार दिया गया है। इस तरह की राहत से इनकार करने का कोई तर्क नहीं है, जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ दायर किया और जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की। इस तरह का सवाल कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होने की संभावना है और हम निर्देश देते हैं कि इस मामले के कागजात एक बड़ी पीठ के गठन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाएं।

अधिनियम की धारा 28-ए, जिसके लिए व्याख्या की आवश्यकता है, निम्नानुसार है: –

"न्यायालय के फैसले के आधार पर मुआवजे की राशि का पुन: निर्धारण।

(1) जहां इस भाग के अधीन अधिनिर्णय में, न्यायालय आवेदक को धारा 11 के अधीन कलेक्टर द्वारा प्रदत्त राशि से अधिक मुआवजे की किसी भी राशि की अनुमति देता है, धारा 4, उपधारा (1) के अधीन उसी अधिसूचना द्वारा कवर की गई अन्य सभी भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति और जो कलेक्टर के निर्णय से भी व्यथित हैं। भले ही उन्होंने धारा 18 के तहत कलेक्टर के लिए आवेदन नहीं किया था, अदालत के फैसले की तारीख से तीन महीने के भीतर कलेक्टर को लिखित आवेदन द्वारा यह आवश्यक है कि उन्हें देय मुआवजे की राशि को न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि के आधार पर फिर से निर्धारित किया जाए:

बशर्ते कि तीन महीने की अवधि की गणना करने पर जिसके भीतर कलेक्टर को आवेदन किया जाएगा

इस उप-धारा के तहत, जिस दिन पुरस्कार सुनाया गया था और पुरस्कार की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाएगा।

1. अधिनियम की धारा 28-ए के शब्दों के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि धारा में यह नहीं कहा गया है कि जिन व्यक्तियों ने अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदन दायर किया है, वे अधिनियम की धारा -28-ए के तहत आवेदन करने के हकदार नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 28-A ऐसे भूस्वामियों को अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ ो की मांग करने से नहीं रोकती है, जिन्होंने अधिनियम की धारा 28-A के प्रावधानों का लाभ उठाने से अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा है। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को (उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार वांछित राहत से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा था। उनके अनुसार, चाहे भूमि मालिकों ने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा हो या नहीं, सभी के साथ समान स्तर पर व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके साथ अलग-अलग व्यवहार करने का कोई

तर्क नहीं है। वकील के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर एक अलग वर्गीकरण में नहीं रखा जा सकता है कि उन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग की है।

2. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 28-ए के स्पष्ट शब्दों को देखते हुए ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा है और जो उच्च न्यायालयों में नहीं गए हैं, वे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर मुआवजे की राशि के पुन: निर्धारण के हकदार नहीं हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि केवल वे व्यक्ति अधिनियम की धारा 28-ए के प्रावधानों का लाभ उठाने के हकदार हैं जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत कलेक्टर को आवेदन दायर नहीं किया था।

(8) प्रतिवादियों के वकील ने *मेवा राम (मृतक) पर उनके एलआर और अन्य लोगों द्वारा भरोसा किया* है। *भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, गुरकाओं* (1), *अनुसूचित जाति सहकारी भूमि दायित्व सोसायटी लिमिटेड, भटिंडा* बनाम *हरियाणा राज्य के माध्यम से हरियाणा राज्यभारत संघ* और अन्य (2), *बाबू राम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक और* अन्य) *और भारत संघ और दूसरा* v. *प्रदीप कुमारी और अन्य* (4)।

1. (1986)4 एससी मामले 151.
2. ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 738.
3. 1995 (2) एससी मामले 689।
4. (1995)2 एससी मामले 730।

1. केस लॉ को नोटिस करने से पहले, जिसे उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत किया गया है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 28-ए में उपयोग किए गए शब्दों के सादे अर्थ के अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति ही पुनर्निर्धारण के हकदार हैं जिन्होंने पहले अधिनियम की धारा 18 के तहत कलेक्टर को आवेदन दायर नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, ऐसे पीड़ित व्यक्ति *जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत कलेक्टर के समक्ष आवेदन दायर नहीं किया था, वे अधिनियम की धारा 28-ए को लागू करने के हकदार हो जाते हैं। अधिनियम की धारा 28-ए, हमारे सुविचारित विचार में, स्पष्ट रूप से परिकल्पना करती है कि केवल उन व्यक्तियों को अधिनियम की धारा* 28-ए के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार है जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ नहीं मांगा था। ऐसे भूस्वामी जिन्होंने संदर्भ के लिए आवेदन नहीं किया था, उन्हें अन्य भूस्वामियों के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग की थी। धारा के स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय मामले के औचित्य पर विचार करने के लिए अनिच्छुक होगा।

1. केस लॉ की बात करें तो *मेवा राम का मामला* (सुप्रा) पहली बार में संदर्भित किए जाने के योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में कहा था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में अधिनियम की धारा 28-क के अलावा किसी अधिनिर्णय को पुन खोलने का **कोई प्रावधान नहीं** है जो अंतिम और निर्णायक बन गया है और अधिनियम की धारा 28-क में मुआवजे की राशि के पुन निर्धारण का प्रावधान है बशर्ते उसमें निर्धारित शर्तें पूरी की गई हों। यह माना गया कि इस तरह के पुन: निर्धारण के लिए मंच कलेक्टर है और पुन: निर्धारण के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार उन व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन नहीं किया था। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में कोई भी अन्य दृष्टिकोण, विनाशकारी परिणामों का कारण बनेगा जो विधायिका द्वारा इरादा नहीं किया गया था।

1. *अनुसूचित जाति सहकारी भूमि स्वामित्व समिति के मामले* (सुप्रा) में, जो इस न्यायालय के एक निर्णय से उत्पन्न हुआ है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अधिनियम की नई जोड़ी गई धारा 28-ए उस मामले पर लागू नहीं होगी जहां दावेदार ने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा है और प्राप्त किया है और यहां तक कि मेवा राम के मामले में की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए उच्च न्यायालय के लिए एक माफी भी पसंद की है । उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की :-

"धारा 28-ए की उप-धारा (1) को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि, यह केवल उन दावेदारों पर लागू होता है जो अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ प्राप्त करने में विफल रहे थे। अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ में न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे के आधार पर कलेक्टर के साथ पुनर्निर्धारण किया जाना है और उस संबंध में एक आवेदन कलेक्टर को पुरस्कार की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाना है। इस प्रकार केवल वे दावेदार जो अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन करने में विफल रहे थे, वे पुनर्निर्धारण के लिए कलेक्टर को आवेदन करने

के इस अधिकार से चिंतित हैं और याचिकाकर्ताओं जैसे सभी नहीं जिन्होंने न केवल धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग की थी, बल्कि संदर्भ न्यायालय द्वारा किए गए फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील भी दायर की थी। इसलिए, नई जोड़ी गई धारा 28-ए स्पष्ट रूप से उस मामले पर लागू नहीं होती है जहां दावेदार ने धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा है और यहां तक कि उच्च न्यायालय में अपील को प्राथमिकता दी है। यह दृष्टिकोण, जिसे हम धारा 28-क के सादे पाठ पर लेते हैं, को मेवा राम (मृतक) से उनके एलआर द्वारा समर्थन मिलता *है/* हरियाणा *राज्य,* 1986) 3 एस.सी.आर.

1. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने *बबुअन राम के* मामले (सुप्रा) और अनुसूचित जाति सहकारी भूमि स्वामित्व समिति *के मामले (*सुप्रा) का *विस्तृत संदर्भ देने के बाद* स्पष्ट रूप से कहा कि अधिनियम की धारा 28-ए की उप-धारा (1) केवल उस व्यक्ति पर लागू होगी जो अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ प्राप्त करने और सुरक्षित करने में विफल रहा, जब एक या अन्य व्यक्ति उसी अधिसूचना के तहत कवर की गई भूमि में समान रूप से रुचि रखते हैं। अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संदर्भ पर प्राप्त मुआवजा अधिनियम की धारा 261 के अंतर्गत अधिनिर्णय में अधिक मुआवजा प्राप्त होता है। भूस्वामियों के वकील की इस दलील का जवाब भी बबुआ राम के मामले (सुप्रा) में शीर्ष अदालत ने दिया है कि 11 भूस्वामियों ने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा है या नहीं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके साथ अलग व्यवहार करने का कोई औचित्य नहीं है । यह आगे माना गया है कि अधिनियम की धारा 28-ए उचित और निष्पक्ष है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है। अनुच्छेद 36 से 38 में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां, जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर सभी चार पर लागू होती हैं -

36. “अगला प्रश्न यह है कि क्या कोई इच्छुक व्यक्ति जिसने धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग की और उसे सुरक्षित किया, लेकिन या तो असफल रहा और उसने कोई अपील दायर नहीं की या अपील की, लेकिन असफल रहा, वह धारा 54 के तहत या आगे अपीलीय न्यायालय द्वारा मुआवजे को बढ़ाए जाने पर पुन: निर्धारण का हकदार होगा।

संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 136 के तहत अपील। मेवा राम मामले में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 5 में कहा कि धारा 28-ए में मुआवजे की राशि के निर्धारण का प्रावधान है, बशर्ते उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाए। इस तरह के पुन: निर्धारण के लिए, मंच कलेक्टर है और धारा 26 के तहत पुरस्कार की तारीख से 30 दिनों के भीतर उनके समक्ष आवेदन करना होगा और यह अधिकार उन व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन नहीं किया था। यदि ये शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 28-ए के तहत प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठा सकता था। अनुसूचित जाति सहकारी भूमि स्वामित्व समिति लि में, *भारत संघ इस न्यायालय ने कहा कि* (एससीसी पी 178, पैरा 4):

> "धारा 28-ए की उप-धारा (1) को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि यह केवल उन दावेदारों पर लागू होता है जो अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ प्राप्त करने में विफल रहे थे। अधिनियम की धारा 18 एफ) के तहत संदर्भ में अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे के आधार पर कलेक्टर द्वारा पुन: निर्धारण किया जाना है और उस संबंध में एक आवेदन कलेक्टर को पुरस्कार की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाना है। इस प्रकार, केवल वे दावेदार जो अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन करने में विफल रहे थे, उन्हें पुनर्निर्धारण के लिए कलेक्टर को आवेदन करने का अधिकार दिया जाता है और याचिकाकर्ताओं जैसे सभी नहीं जिन्होंने न केवल धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा था, बल्कि उच्च न्यायालय में अपील भी दायर की थी ।

यह भाग II और III में अधिनियम की योजना और विशेष रूप से धारा 28A में स्व-निहित संहिता को पढ़ने से भी स्पष्ट है: यह पहले से ही माना गया है, कि एक इच्छुक व्यक्ति जिसने विरोध के बिना मुआवजा प्राप्त किया है, वह पीड़ित व्यक्ति बन जाता है जब धारा 4 (1) के तहत उसी अधिसूचना द्वारा कवर की गई भूमि में रुचि रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को सिविल कोर्ट से अपनी भूमि के लिए अधिक मुआवजा मिलता है। धारा 28 ए (1) के भीतर गैर-बाध्यकारी खंड का जैव संचालन, धारा 18 (1) द्वारा बनाए गए प्रतिबंध और उपधारा (2) के दूसरे परंतुक। धारा 31 को हटा दिया गया है और उसे धारा 28-ए के तहत अधिकार और उपाय दिया गया है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने विरोध के तहत मुआवजा प्राप्त किया और संदर्भ मांगा और प्राप्त किया, लेकिन असफल या आंशिक रूप से सफल रहा, धारा 18 (1) और धारा की उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक द्वारा बनाए गए प्रतिबंध के भीतर आता है। धारा 31 और- धारा 28-ए (एल) में गैर-बाध्यकारी खंड नहीं है

उसे इससे छुटकारा दिलाएं। विधायिका ने गरीब और मुखर लोगों के बीच एक भेदभावपूर्ण नीति बनाई, क्योंकि एक वर्ग का व्यक्ति जिसे धारा 28 ए का लाभ दिया जाना था और तुलनात्मक रूप से समृद्ध जिसने धारा 18 के तहत संदर्भ का लाभ उठाया था और बाद में एक वर्ग के रूप में जिसे धारा 28-ए का लाभ नहीं दिया गया था। अन्यथा, गैर-बाध्यकारी खंड की भाषा के भ्रम विज्ञान को अलग-अलग शब्दों में कहा गया होता, यानी "इसके बावजूद कि उन्होंने धारा 18 के तहत कलेक्टर को आवेदन नहीं किया था या धारा 54 या अनुच्छेद 132, 133, 136 के तहत अपील नहीं की थी या असफल रही थी। ऐसी भाषा नहीं है। संशोधन अधिनियम की धारा 30 के संक्रमणकालीन प्रावधान ही दावेदारों के बीच भेदभाव करते हैं, जिनके पक्ष में कलेक्टर या अदालत आदि द्वारा निर्णय दिया गया था, जैसा कि निर्णय के पहले भाग में धारा 30 की उप-धाराओं (1) से (3) के प्रभाव से निपटने के दौरान पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। इस प्रकार संसद ने व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान में भेदभाव किया, हालांकि संशोधन अधिनियम के विभिन्न लाभों के लिए समान रूप से स्थित है। यहां तक कि धारा 23 (1) के तहत मुआवजे का भुगतान अलग-अलग है, जो समान मूल्य प्राप्त करने में सक्षम भूमि की समान गुणवत्ता या निकटता में स्थित भूमि का मूल्य और बाजार मूल्य का भुगतान समान नहीं है। सी.पी.सी. की धारा 11 के तहत न्याय का सिद्धांत ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ काम करता है। एक सक्षम सिविल कोर्ट में उपाय का पीछा करने और धारा 26 या धारा 54 के तहत डिक्री को अंतिम रूप देने की अनुमति देने के बाद, यह पार्टियों और राज्य को बांधता है और एक *न्याय-न्यायालय* का संचालन करता है और वह धारा 28-ए की उप-धारा (1) के तहत अधिकार और उपाय से पीछे नहीं हट सकता है क्योंकि सार्वजनिक नीति की परिकल्पना यह है कि ऐसी पार्टी अपने अधिकार को दो बार आंदोलन नहीं कर सकती है। इसलिए, धारा 28-ए की उप-धारा (1) द्वारा धारा 4 (1) के तहत उसी अधिसूचना द्वारा कवर की गई अन्य भूमि में रुचि रखने वाले गरीब और अस्पष्ट व्यक्तियों को अधिकार और उपाय उपलब्ध कराया गया और धारा 28-ए (एल) के तहत अधिकार और उपाय का लाभ उठाने के लिए धारा 18 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया। लेकिन जिन लोगों ने धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा और प्राप्त किया, चाहे वे गरीब हों या अन्य, और सिविल कोर्ट के समक्ष या धारा 54 या अनुच्छेद 136 आदि के तहत अपील में विफल रहे, धारा 28-ए (1) द्वारा प्रदान किए गए अधिकार और उपाय उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, धारा 28ए का संचालन केवल भाग III में किए गए निर्णय तक ही सीमित है, न कि संविधान के अनुच्छेद 132, 133 या 136 के तहत धारा 54 के तहत उच्च न्यायालय या अपीलीय अदालत या इस न्यायालय के निर्णय या डिक्री तक। इसलिए, असफल इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने धारा 18 के तहत या धारा 54 के तहत या अनुच्छेद 136 आदि के तहत अपील में मांग की और असफल रहे, वे धारा 28-ए की उप-धारा (1) के तहत पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं, जब अन्य समान हों।

उस उपाय का पालन करने से व्यक्ति को अधिक मुआवजा मिला था। इसलिए, वह या वे, हालांकि धारा 4 (1) के तहत उसी अधिसूचना द्वारा कवर की गई भूमि में रुचि रखते हैं, धारा 28-ए, 37 की उप-धारा (1) के तहत पुनर्निर्धारण के लिए आवेदन / आवेदन करने के हकदार नहीं हैं। अगला सवाल यह है कि क्या धारा 28-ए की उप-धारा (1) के तहत इस तरह के अधिकार और उपाय से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह सच है कि विधायिका का उद्देश्य गरीब, गरीब और मुखर इच्छुक व्यक्तियों को कठिनाई से राहत देना था, जो आम तौर पर धारा 18/जो एक मौजूदा बार के तहत संदर्भ का लाभ उठाने में विफल रहे हैं और इसे दूर करने के लिए, धारा 28 ए को पुनर्निर्धारण के लिए अधिकार और उपाय देते हुए लागू किया गया था, जब किसी अन्य व्यक्ति को धारा 11 के तहत दिए गए

मुआवजे से अधिक धारा 26 के तहत अधिक मुआवजा मिला था। दूसरे शब्दों में, क़ानून उसे अपने अधिकार के प्रति सचेत करता है, भले ही यह धारणा हो कि, हर कोई जानता है कि कानून उसके खिलाफ जाता है और धारा 18 के तहत अधिकार और उपाय का लाभ उठाने में विफल रहता है।। फिर भी धारा 28ए स्वयं को वही राहत देती है। समान व्यक्तियों का वर्ग जिन्होंने सही और उपचार का लाभ उठाया लेकिन असफल रहे, उन्हें एक अलग वर्ग के रूप में माना जाता है। यह किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। इसे मनमाना कहा जाता है क्योंकि वर्गीकरण समझदार भिन्नता पर आधारित है और किसी अन्य अवसर के उद्देश्य से उचित संबंध रखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका ने यह मान लिया है कि गरीब और अस्पष्ट व्यक्तियों के बीच भी यही स्थिति बनी हुई है और वे आम तौर पर गरीबी या अज्ञानता या निष्कासन से बचने के कारण धारा 18 की उप-धारा (1) के तहत अधिकार का लाभ उठाने में विफल रहते हैं। यह पहले से ही देखा गया है कि, संसद ने गरीब और अव्यक्त वर्ग और तुलनात्मक रूप से समृद्ध वर्ग के बीच सचेत भेदभाव किया: एक अन्य वर्ग के रूप में और धारा 28-ए के तहत अधिकार पूर्व के पक्ष में प्रदान किए। संशोधन अधिनियम के संक्रमणकालीन प्रावधानों की धारा 30 में भेदभाव स्पष्ट है, जिसमें विभिन्न स्थितियों द्वारा कवर किए गए मुआवजे और अतिरिक्त, मुआवजे का भुगतान प्रदान किया गया है, हालांकि इच्छुक व्यक्ति एक ही वर्ग के हैं। धारा 28-ए उचित और निष्पक्ष है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है। इसलिए, प्रक्रिया उचित और निष्पक्ष है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है। तथापि, अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव से बचने की दृष्टि से, यह उचित होगा कि धारा 31 के अधीन क्षतिपूत का भुगतान करते समय कलेक्टर को दावाकर्ता की स्थानीय भाषा में स्पष्टीकरण देना चाहिए और मुआवजे में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित करना चाहिए कि उन्हें धारा 11 के अधीन निर्धारित मुआवजे के विरुद्ध विरोध करने का अधिकार है। सिविल कोर्ट को धारा 18 के तहत लिखित रूप में संदर्भ प्राप्त करने का अधिकार है और यह कि आवेदन धारा 18 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर लिखित में विशिष्ट आपत्तियों को व्यक्त करते हुए किया जाना चाहिए। . यदि वह इसका लाभ उठाने में विफल रहता है, तो वह अधिक मुआवजे की मांग करने के लिए आगे के अधिकार और उपाय का हकदार नहीं होगा **। :में**

यदि दावेदार अनपढ़ है, तो उसे उसकी मातृभाषा में ठीक से समझाया जाना चाहिए। कलेक्टर द्वारा इस संबंध में दिया गया बयान- दावेदार की मातृभाषा में होना चाहिए। कलेक्टर को एक प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए कि यह वास्तव में, सही ढंग से और ठीक से समझाया गया था और उस पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करना चाहिए और इसे पुरस्कार कार्यवाही के रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में रखा जाना चाहिए। उसे अपने कार्यालय में एक नियमित रजिस्टर भी रखना चाहिए जो उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सील किया गया हो और कलेक्टर की व्यक्तिगत हिरासत में रखा जाए। इससे न केवल इच्छुक व्यक्तियों को होने वाली कठिनाई को कम किया जा सकेगा, बल्कि सीमा की सीमा के बाद संदर्भ के लिए आवेदन तैयार करने में भ्रष्ट प्रथाओं को भी रोका जा सकेगा। इस संबंध में, यह भी आवश्यक है कि कलेक्टर/एलएओ को धारा 28-ए के तहत आवेदनों की प्राप्ति के लिए एक और रजिस्टर भी रखना चाहिए, जिसमें इसकी प्राप्ति की तारीख, संबंधित कलेक्टर/एलएओ के कार्यालय की मुहर और व्यक्तिगत हस्ताक्षर और अधिनियम की धारा 11 के परंतुक में सरकार या अधिकृत अधिकारी को विधिवत सूचित किया गया हो।

1. *प्रदीप कुमार* के *मामले* (सुप्रा) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर से कहा कि व्यक्ति उसे देय मुआवजे की राशि के पुनर्निर्धारण की मांग कर सकता है

बशर्ते वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो। उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों में से एक यह है कि आवेदन करने वाले व्यक्तियों ने अधिनियम की धारा 18 के तहत कलेक्टर को आवेदन दायर नहीं किया था।

1. शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, जो अधिनियम की धारा 18 के स्पष्ट और स्पष्ट शब्द हैं, यह सुरक्षित रूप से दोहराया जा सकता है कि धारा 28-ए केवल उन दावेदारों पर लागू होगी जो अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ प्राप्त करने में विफल रहते हैं। जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग की थी, क्या ऐसे भूस्वामी अंततः उच्च न्यायालयों में अपील में गए थे या नहीं। दूसरे शब्दों में^, अधिनियम की धारा 28-ए के तहत पुनर्निर्धारण का अधिकार केवल उन भूमि-मालिकों तक ही सीमित है, जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ नहीं मांगा था। अनुसूचित *जाति सहकारी लैंड ओइंग सोसाइटी लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों (*फैसले के पहले भाग में हमारे द्वारा पुन: प्रस्तुत) के मद्देनजर भूमि-मालिकों के एक समूह, जिन्होंने संदर्भ प्राप्त किया और दूसरे सेट, जिन्होंने संदर्भ प्राप्त नहीं किया और इसके पीछे के तर्क के बीच भेदभाव के बिंदु पर याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील को बिल्कुल भी बल नहीं मिला है।

1. इस स्तर पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भू-स्वामियों के वकील ने हमसे इस आधार पर मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया कि *जोस एंटोनियो क्रूज़ डॉस आर रॉड्रिग्स के मामले में संदर्भ दिए जाने के कारण सर्वोच्च न्यायालय फिर से इस मामले की सुनवाई कर रहा है* । *भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और एक अन्य* (5)।

2. हमने पूरे फैसले का अध्ययन किया है। हमारे सुविचारित विचार में, कानून का सटीक प्रश्न, जो हमारे समक्ष इन मामलों में उठा है, और जिस पर हमने विचार किया है, बड़ी पीठ के समक्ष विचारार्थ विषय नहीं है। *जोस एंटोनियो के मामले* (सुप्रा) में शीर्ष न्यायालय द्वारा केवल दो प्रश्न इस प्रकार हैं: -

"(1क्या धारा 18 के तहत संदर्भ पर धारा 26 के तहत किए गए न्यायालय यानी सिविल कोर्ट के फैसले में धारा 54 के तहत अपीलीय न्यायालय का निर्णय और डिक्री भी शामिल होगी?

(2) **क्या** प्रत्येक क्रमिक निर्णय या निर्णय और डिक्री (यदि प्रश्न पर उत्तर सकारात्मक है) धारा 28-ए के तहत आवेदन दायर करने के लिए कारण कार्रवाई करेगा; यदि ऐसा माना जाता है, तो क्या ऐसा निर्माण धारा 28-ए में उपयोग की जाने वाली भाषा का उल्लंघन नहीं करता है; जब संसद ने सलाह दी थी कि ऐसी अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है। " .

1. फैसले से अलग होने से पहले 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 15196 में श्री आर. के. बट्टस की दलीलें देना आवश्यक है *(शाम कौर और अन्य* बनाम 1996)। *पंजाब राज्य)* / यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के मामले को अलग से निपटाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष क्रॉस-आपत्तियां दायर की थीं और जिला न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की थी।

आगे यह तर्क दिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बलवंत सिंह और अन्य की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं के रूप में ऐसे व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने का इरादा किया *था* । *पंजाब का बासी।* उच्चतम न्यायालय का आदेश इस स्तर पर विशेष उल्लेख के योग्य है जो निम्नानुसार है:-

पीठ ने कहा, "विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं। दो पहलुओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए। कुछ दावेदारों को विशेष अनुमति याचिकाओं (एलपीए संख्या 1135/82 में) में याचिकाकर्ता संख्या 9-15 कहा जाता है।

(5) ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 709.

उन्होंने कोर्ट ऑफ रेफरेंस के फैसले के खिलाफ अपील को प्राथमिकता नहीं दी थी। जब राज्य ने एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी, तो उन्होंने क्रॉस आपत्तियां दर्ज कीं और उन्हें इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उन्होंने कोर्ट ऑफ रेफरेंस के फैसले को चुनौती नहीं दी थी। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संशोधन अधिनियम, 1984 के तहत उपलब्ध लाभ क्रॉस-आपत्तियों को खारिज करने के कारण प्रभावित नहीं हो सकते हैं और याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला होगा कि वे बढ़े हुए मुआवजे के लाभों का दावा करने के लिए प्राधिकरण के समक्ष जाएं और अधिकारी कानून के अनुसार मामले से निपटने के लिए स्वतंत्र हैं।

संविधान पीठ के यह मानने की स्थिति में कि संशोधन अधिनियम के लाभ तथ्यों के सेट में उपलब्ध हैं, याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए कहने और 1984 संशोधन अधिनियम के लाभों का दावा करने के हकदार हैं।

1. उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का अध्ययन करने के बाद, हम श्री बट्टस के साथ सहमत होने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। अधिनियम की धारा 18 के तहत जिला न्यायाधीश की अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर धारा 28-ए के तहत लाभ प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा। यहां तक कि अगर याचिकाकर्ता शाम, कौर आदि ने क्रॉस-आपत्तियां दर्ज नहीं की थीं, तो वे अधिनियम की धारा 28-ए के तहत पुनर्निर्धारण के हकदार नहीं थे। क्या शाम कौर आदि द्वारा राहत का दावा किया गया था? उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करना या क्रॉसएक्टिजेक्शन दर्ज करने का तरीका, यह एक ही बात है। इन सबसे ऊपर, अंतत उच्चतम न्यायालय का निर्णय दावेदारों के विरुद्ध गया है और इसलिए। शाम कौर आदि बलवंत सिंह और अन्य की विशेष अनुमति याचिका में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के कारण अलग-अलग स्तर पर नहीं खड़ी होती हैं, जिन्हें हमारे द्वारा विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

1. ऊपर दर्ज कारणों के लिए रिट याचिकाओं को किसी भी योग्यता से रहित पाया जाता है और उन्हें लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

जे. एस. टी.,

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अवीषेक गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा